HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 13966/2026
CNR: RJHC010636072026
URN: CW / 25448U / 2026

Ram Bharosi Gurjar S/o Shri Chand Gujar, Aged About 52 Years, R/o Village Vidrakhya, Tehsil Gangapur City, District Sawai Madhopur (Raj.) (Presently Working As Block Coordinator Under Swachh Bharat Mission, (Grameen), At Panchayat Samiti Bamanwas, Distt. Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, through The Principal Secretary, Rural Development And Panchayati Raj Department, Government Of Rajasthan, Jaipur. (Raj.)
2. Commissioner, Rural Development And Panchayati Raj Department, Government Of Rajasthan, Jaipur. (Raj.)
3. Director, Swachh Bharat Mission (Grameen), Panchayati Raj Department, Near Railway Station, Jaipur (Raj.)
4. Chief Executive Officer And Member Secretary, District Sanitation Mission, District Sawai Madhopur, Rajasthan.
5. Association For Rural Advancement, through Voluntary Action And Local Involvement (Aravali), Through Its Programme Director, First Floor, Ministerial Campus, Indira Ganghi Panchayati Raj And Grameen Vikas Sansthan (IGPRS) Campus Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur (Raj.)
6. Gopal Meena S/o Shri Bardi Chand Meena, Block Coordinator Under Swachh Bharat Mission, (Grameen) At Panchayat Samiti Bamanwas, Distt. Sawai Madhopur).

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Hukam Singh, Adv.
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

08/07/2026

विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि अयाची संख्या 05 प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से याची जून 2026 तक अपनी सेवाएं अयाची संख्या 01 से 04 विभाग में दे रहा था। प्लेसमेंट एजेंसी राज्य द्वारा शासित है,

याची के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की सेवा लिये जाने की संभावना को देखते हुए याची की ओर से S.B. Civil Writ Petition No. 1560/2026 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 23.01.2026 को यह आदेश दिया गया था कि समान प्रकृति के दूसरे कर्मचारियों को याची के स्थान पर नियोजित नहीं किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता याची का यह निवेदन है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 23.01.2026 के बावजूद व उसके उल्लंघन में जुलाई 2026 से याची–कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई है और उसके स्थान पर अयाची संख्या 06 गोपाल मीणा को सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु चयनित किया गया है।

उपरोक्त तथ्य रखते हुए याची पक्ष की ओर से यह निवेदन किया कि उसकी सेवाएं निरंतर रखे जाने का आदेश दिया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत निम्नानुसार प्रस्तुत किये हैंः–

1. Barinder Kaur Vs. Guru Nanak Dev University Amritsar & Ors. 2015 SCC Online P & H 12156
2. State of Haryana & Ors. Vs. Piara Singh & Ors. (1992) 4 SCC 118
3. Hargurpratap Singh Vs. State of Punjab & Ors. (2007)13 SCC 292

एवं इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा Civil Writ Petition No. 12054/2025, Govind Ram Yadav & Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors. में पारित आदेश दिनांक 01.04.2026 तथा S.B. Civil Writ Petition No. 13629/2026, Ramesh Chandra Nayak & Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors. में पारित आदेश दिनांक 06.07.2026 प्रस्तुत किये।

यदि पूर्ववर्ती न्यायिक आदेश दिनांक 23.01.2026 की अवहेलना में कोई नियुक्ति हुई है तो इस संबंध में याची अवमानना याचिका प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

वर्तमान में यह स्वीकृत स्थिति है कि उसकी सेवाएं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से दिनांक 01 जुलाई, 2026 से समाप्त की जा चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2009) 17 SCC 555 State of UP & Ors. V/s. Sandeep Kumar Balmiki & Ors. के मामले में प्रतिपादित व्यवस्था के

अनुसार स्थगन याचिका में अंतिम अनुतोष प्रदान किया जाना उचित नहीं है, इस निर्णय का सुसंगत भाग नियमानुसार हैः—

> "We have heard Mr. S.R. Singh, learned senior counsel appearing for the State of UP and Mr. P.S. Patwalia, learned senior counsel appearing on behalf of the respondents. Having heard the learned senior counsel for the parties and after considering the impugned orders as well as the nature of relief claimed in the writ petition by the respondents, we are of the view that the High Court had fallen in grave error in staying the order of termination during the pendency of the writ petition. In our view, the interim order granted by the High Court staying the order of termination could not be passed at this stage in view of the fact that if such relief is granted at this stage, the writ petition shall stand automatically allowed without permitting the parties to place their respective cases at the time of final hearing of the writ petition. In this case also, the appellants have not yet filed counter affidavit to the writ petition of the respondents."

उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए इस स्टेज पर अयाचीगण को सुने बिना कोई स्थगन आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

याचिका व स्थगन याचिका के नोटिस सभी अयाचीगण को नियमानुसार जारी होकर प्रकरण चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

98-Kumawat